

संपादकीय

यह कैसी कृतनीति

वा इत हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और युक्तीनी राष्ट्रपति जेलेस्की के बीच शुक्रवार को जिस तह की तीखी नोकझोक देखने को मिली, उसे कृतनीति के इतिहास में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। लाइव टीवी कवरेज के जरिए पूरी दुनिया ने घली बार देखा कि दो राष्ट्राध्यक्ष अपनी टीम के साथ एक-दूसरे से तू-तू मैं-मैं कर रहे हैं।

बात सही, तरोका गलत : वैसे, दोनों पक्षों के स्टेंड पर गौर करें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती जिसे सिरे से गलत कहा जाए। रूस-यूक्रेन युद्ध को तीन साल से ज्यादा हो रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध में लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अब अगर उसे लगता है कि अपने देश के करताराओं का पैसा इस लड़ाई में नहीं ज्ञोका जाना चाहिए, तो इसमें कूल भी असंत नहीं है। इस लिहाज से उसकी यह कोशिश जायज है कि यह लड़ाई जल्द से जल्द बंद हो।

सुरक्षा गारंटी का सावल : दूसरी तरफ, यूक्रेन यह सुनान्शित करना चाहता है कि युद्धविराम के बाद रूस फिर से हमला न करें। कारण यह जो बैठे, उसकी यह शिकायत तथ्यात्मक रूप से सही है कि रूस अलग-अलग बहानों से उस पर हमले करता रहा है, सहमतियां तोड़ता रहा है। ऐसे में जहां अमेरिका पहले समझौता और

दो देशों के बीच सहमति बनने से पहले इस तरह का गतिशील आना कोई नहीं था। नवी बात यह हुई कि इन मतभेदों पर वर्षा मिडिया के साथने शुरू हो गयी। चूंकि बातचीत वाइट हाउस में हो रही थी, इसलिए स्वाभाविक ही इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर आ जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध भी उत्तीर्ण इसमें इसकी वार्ता करने के बाद रुसी नोकझोक को ग्रेट रेलिंगिं जल्द करार दिया।

आगे क्या : मकसद चाहे जो भी रहा हो, इस पूरे प्रकरण से दोनों में से कोई भी सूक्ष्म फाफदे में नहीं दिख रहा।

अमेरिका जो समझौता यूक्रेन के साथ करना चाहता था, वह टल गया। यूक्रेन को भले ही यूरोप का साथ मिलता दिख रहा है, अमेरिकी समर्थन के बगैर उसका इस युद्ध में टिकना मुश्किल है। ऐसे में बहुत सभ्य है कि देश-सर्वर दोनों फिर बातचीत की टेबल पर आ जाएं। बेहतर होना कि इंतजार में ज्यादा वक्त और जिंदगियां न बर्बाद की जायें।

अभिमत आजाद सिपाही

ब्लूम वैर्स की इंडस वैली की वार्षिक रिपोर्ट 2025 भारत की आर्थिक विषयता की यह तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट का सरकार द्वारा किसी तरह प्रतिवाद नहीं किये जाने से साफ़ जाहिर है कि देश की आर्थिक सेहत एकत्रणा जा रही है। अमीरी और गरीबी की खाई का पौड़ा होना जारी है। रिपोर्ट में इस बात पर अतिरिक्त खर्च करने में असरहृष्ट है। लोग जरूरत के अलावा सामान या सुविधाएं नहीं खरीद सकते। वही, देश के केवल 10 फीसदी लोग, अर्थात् 13-14 करोड़ लोग देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग ही सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और देश की तरकीकी में बड़ा रोल निभाते हैं। केंद्र सरकार एक तरफ देश में तात्कालीन नया मॉडल पेश करते हुए विकसित भारत की तरफ बदल कर्दमों का आकड़ा पेश करती है, वहीं गरीबी और अमीरी की बढ़ती खाई ने इस मॉडल पर सवालिया निशान लगा दिये हैं।

ब्लूम वैर्स की इंडस वैली की वार्षिक रिपोर्ट 2025 भारत की आर्थिक विषयता की यह तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट का सरकार द्वारा किसी तरह प्रतिवाद नहीं किये जाने से साफ़ जाहिर है कि देश की

आर्थिक सेहत एकत्रणा जा रही है। अमीरी और गरीबी की खाई का चौड़ा होना जारी है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का उपभोक्ता बाजार बढ़े रहा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

है कि भले ही अमीर लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग पहले से ही अमीर हैं, वे और भी अमीर हो रहे हैं। आकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) के पास अब कुल नेशनल आय का 57.7 प्रतिशत दिस्ता है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले के 22.2 प्रतिशत से घट कर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा।

आकड़ों के मुताबिक 5 साल पहले रियल एस्टेट की कुल बिक्री में अपोर्डेबल हाऊसिंग की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी, जो अब घटकर महज 18 प्रतिशत रह गयी है। इस महीने पेश हुए बजट में वित मंत्री

निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग की जेब ढीली करने के लिए टैक्स में छूट दी। 12 लाख रुपये तक कमाई करने वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा जिससे 92 प्रतिशत वेतनभोगी लोगों को राहत मिलेगी। इसके बावजूद भारत की खपत चीन से 13 साल पीछे है।

वर्ष 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति खर्च 1,493 डालर था, जबकि चीन में वर्ष 2010 में ही ये 1,597 डालर था।

है कि भले ही अमीर लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग पहले से ही अमीर हैं, वे और भी अमीर हो रहे हैं। आकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर

भारतीय) की अर्थव्यवस्था को इंडियन रेस्टॉरंट घर के लिए बड़ी खाई होता है। श्री दास ने आरोप लगाया वर्तमान सरकार अब दिन में सपने देख रही है। 'अबुआ बजट' में 'अबुआ' को ही किनारे कर दिया गया। उनके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि और अपूर्जी बाजार की वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

उदारीकरण के बाद से सेवा की अगुवाई में हुई आर्थिक वृद्धि के भी असमान असर हुए। इस पूरे हालात से साफ़ है कि भारत की खपत ग्रोथ संतुलित नहीं है। एक तरफ जहां अमीर और अमीर हो रहे हैं, वहीं गरीब और गरीब, जिसके लिए आपने वाले समय में सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

उदारीकरण के बाद से सेवा की अगुवाई में हुई आर्थिक वृद्धि के भी असमान असर हुए। इस पूरे हालात से साफ़ है कि भारत की खपत ग्रोथ संतुलित नहीं है। एक तरफ जहां अमीर और अमीर हो रहे हैं, वहीं गरीब और गरीब, जिसके लिए आपने वाले समय में सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे जिससे आर्थिक असमानता कम हो सके।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोला लगाया है। इसके बाबत निजी उद्यम में वृद्धि ने शीर्ष के कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति का सिपाटना बढ़ाया है।

भारतीय आर्थिक विषयता की अवधारणा ने देश के बाबत निजी उद्यम में वृद्धि के काला गोल

